

ख़बर संक्षेप

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में आज अमरपुर में शिविर का आयोजन

उमरिया। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत 11 सितंबर को मानपुर विकासखण्ड मुख्यालय के अमरपुर में अपराह्न 3 बजे से शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर आयोजन से पहले अधिकारियों द्वारा ग्राम अमरपुर, मझोखर, खलौंध, कोटरी, टिकुरी, देवगवाँ, बड़छड़, बचहा, सलेया, मुडगुडी असोड एवं महरोई का भ्रमण किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय सहित जिले के वरिष्ठ विभागीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण करेंगे तथा आम जनों से शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी लेंगे।

माटी गणेश-सिद्ध गणेश अभियान, पर्यावरण संरक्षण का दिया जा रहा संदेश

उमरिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में जन अभियान परिषद एवं नर्मदा समग्र के संयुक्त तत्वावधान में संपूर्ण प्रदेश में माटी गणेश-सिद्ध गणेश अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य गणेश उत्सव के माध्यम से जन-जन तक पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाना और नगरिकों को पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के तहत कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने जिलेवासियों से अपील की है कि गणेश उत्सव के दौरान अपने घरों में मिट्टी से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। उन्होंने कहा कि मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं पर्यावरण के अनुकूल होती हैं तथा इनके विसर्जन से जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने में मदद मिलती है।

विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों तथा न्यायालयीन प्रकरण में लोक अदालत में छुट का प्रावधान

उमरिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, 12 सितंबर को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लोक अदालत में उपभोक्ताओं की पुराने विवादों और बकाये से मुक्ति दिलाने के लिए छूट की घोषणा की गई है। लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों में 30 प्रतिशत की सीधी छूट तथा ऐसे मामले या विवाद जो अभी तक अदालत में दर्ज नहीं हुए हैं, लेकिन विभाग के पास लंबित हैं, उनके निपटारे पर उपभोक्ताओं को मूल राशि (सिविल दायित्व की राशि) में 30 प्रतिशत और ब्याज में पूरे शत प्रतिशत प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार जिला न्यायालय में विचाराधीन या लंबित प्रकरणों में उपभोक्ताओं को आपसी राजीनामे के तहत मूल राशि (सिविल दायित्व की राशि) में 20 प्रतिशत और ब्याज में पूरे शत प्रतिशत विशेष छूट प्रदान कर प्रकरण को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा।

स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना 2026 के तहत जिले में लगेंगे शिविर

उमरिया। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन 2026 योजना के तहत जिले की सात तहसीलों में ग्राम स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रथम शिविर 17 सितंबर को आयोजित होगा, जबकि द्वितीय शिविर 21 सितंबर व तृतीय शिविर 23 सितंबर को आयोजित होंगे। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने बताया कि स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना अंतर्गत प्रथम शिविर 17 सितंबर को 196 ग्रामों में आयोजित किया जाएगा। जबकि द्वितीय शिविर 73 ग्रामों में तथा तृतीय शिविर 32 ग्रामों में आयोजित होंगे। उन्होंने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना एवं कार्य संपादन हेतु अधिकारियों कर्मचारियों को दायित्व सौंप है। जिला स्तर पर संपूर्ण योजना के समयबद्ध निष्पादन हेतु डिप्टी कलेक्टर कमलेश नीरज को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जबकि डिप्टी कलेक्टर प्रत्युष श्रीवास्तव, प्रिया अग्रवाल को मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है जो संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदाय करेंगे।

वार्ड 7 में कछुआ चाल से नाली निर्माण, मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित, पुलिस भी ले सकती है संज्ञान

तीन माह से सड़क पर मलबा जिम्मेदारों की आंखों पर पड़ी

अमलाई। नगर परिषद बकहो के वार्ड क्रमांक 7 स्थित रावल मार्केट में नाली निर्माण के नाम पर करीब तीन माह से सड़क किनारे खोदा गया मलबा पड़ा हुआ है। निर्माण कार्य कछुआ चाल से चल रहा है और सड़क पर बिखरे पथर, मिट्टी एवं निर्माण सामग्री के कारण आम लोगों को मारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग कामल कान्वेंट स्कूल पहुंचने

वाला प्रमुख मार्ग है, जहां से ओपीएम के छात्र-छात्राओं सहित बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। सड़क की स्थिति ऐसी है कि कई जगह दोपहिया वाहन निकालना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में कभी भी दुर्घटना की स्थिति बन सकती है।

उपाध्यक्ष के अपने वार्ड में तीन माह से बढहाली

मामले को लेकर नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि यह मार्ग नगर परिषद उपाध्यक्ष भैवम विक्रम सिंह के वार्ड क्रमांक 7 में है और उनके घर के सामने से होकर गुजरता है। इसके बावजूद सड़क से मलबा हटाने और निर्माण कार्य को गति देने की दिशा में अब तक अपेक्षित कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। जनता का सवाल सीधा है कि जब



जनप्रतिनिधि के अपने वार्ड और घर के सामने मुख्य सड़क की यह हालत है, तो फिर नगर परिषद की निगरानी व्यवस्था आखिर किसके भरोसे चल रही है?

सड़क बाधित होने पर पुलिस भी कर सकती है कार्रवाई

सड़क पर निर्माण सामग्री और मलबा इस तरह पड़ा रहना, जिससे सार्वजनिक आवागमन या यातायात बाधित हो और दुर्घटना की आशंका बने, केवल नगर परिषद की जिम्मेदारी का विषय नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में पुलिस भी अपने अधिकार क्षेत्र में यातायात सुचारु कराने, बाधा हटाने तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए संज्ञान ले सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नगर परिषद निर्माण कार्य पूरा करने में समय लगा रही है तो कम से कम सड़क

को आवागमन योग्य बनाए रखने और मलबे को व्यवस्थित तरीके से हटाने की व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिए।

हादसा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि तीन महीने से सड़क पर मलबा पड़ा होने के बावजूद जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधि अब तक क्यों नहीं जागे? क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है? नगर परिषद को तत्काल मलबा हटवाकर रास्ता सुरक्षित कराना चाहिए। वहीं, यदि सड़क पर अवरोध के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है तो पुलिस प्रशासन को भी मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। जनता को विकास के नाम पर महीनों तक परेशानी नहीं, बल्कि सुरक्षित और सुगम आवागमन चाहिए।

समय सीमा खत्म, फिर भी कछुआ चाल से क्रिकेट बॉक्स निर्माण, सरकारी स्काई लिफ्ट से टेकेदार को ‘सेवा’



वार्ड क्रमांक 2 के पार्श्व ने लगाए गंभीर आरोप, सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल और टेकेदार को कथित लाभ पहुंचाने पर उठाए सवाल

अमलाई। नगर परिषद बरगवां (अमलाई) में निर्माण कार्य और सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2 के पार्श्व ने जिम्मेदार अधिकारियों और टेकेदार की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकारी मशीनरी के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया है।

पार्श्व के अनुसार, वार्ड क्रमांक 3 में निजी फर्म “श्री गणेश एंटरप्राइजेज” द्वारा कराया जा रहा क्रिकेट बॉक्स निर्माण कार्य महीनों से अधर में लटका हुआ है। उनका आरोप है कि अनुबंध के तहत निर्धारित कार्य पूर्ण करने की समय सीमा काफी पहले समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद टेकेदार पर पेनल्टी लगाने या अनुबंध निरस्त करने जैसी कार्रवाई करने के बजाय काम

को कछुआ चाल से आगे बढ़ाया जा रहा है।

समय सीमा खत्म, फिर कार्रवाई क्यों नहीं?

वार्ड क्रमांक 2 के पार्श्व ने सवाल उठाया है कि जब निर्माण कार्य की तय समय सीमा समाप्त हो चुकी है तो जिम्मेदार अधिकारी अब तक टेकेदार पर नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या टेकेदार को अतिरिक्त समय देने का कोई विधिवत आदेश है और यदि है तो उसकी शर्तें क्या हैं? इन सवालों के बीच निर्माण कार्य की धीमी गति को लेकर परिषद की निगरानी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है।

निजी निर्माण में सरकारी स्काई लिफ्ट लगाने का आरोप

पार्श्व ने इससे भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लेटलतीफी के बावजूद संबंधित फर्म को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए नगर परिषद की सरकारी स्काई लिफ्ट गाड़ी और परिषद के कर्मचारी/ड्राइवर को निजी निर्माण कार्य में लगाया जा रहा है।

पार्श्व का कहना है कि परिषद की किसी बैठक या ठहराव में सरकारी वाहन को निजी कार्य में लगाने अथवा किराए पर देने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में सवाल है कि सरकारी वाहन निजी निर्माण स्थल तक किसके आदेश पर पहुंचा और उसके इस्तेमाल का भुगतान किस मद से किया जा रहा है?

‘2-3 घंटे की रसीद’ पर भी सवाल

पार्श्व ने आरोप लगाया कि पूर्व में भी उक्त फर्म को कई बार नियम विरुद्ध तरीके से सरकारी वाहन उपलब्ध कराने की बात सामने आती रही है। उनका दावा है कि जब सरकारी वाहन के इस्तेमाल पर सवाल उठते हैं तो महज 2-3 घंटे की रसीद का हवाला देकर मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, जबकि वाहन के घंटों इस्तेमाल की बात कही जा रही है। यदि सरकारी वाहन का वास्तविक उपयोग निर्धारित अवधि से अधिक हुआ है तो लॉगबुक, वाहन मूवमेंट, ड्राइवर की ड्यूटी और भुगतान संबंधी रिकॉर्ड की जांच से स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

पार्श्व ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की तैयारी बताई

वार्डक्रमांक2केपार्श्वनेपूराममलेकोगंभीरबतातेहुएउच्चाधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है। शिकायत होने पर निर्माण कार्य की समय सीमा, टेकेदार पर की गई कार्रवाई, सरकारी वाहन के उपयोग की अनुमति, वाहन लॉगबुक और संबंधित भुगतान की जांच की मांग उठ सकती है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं और सरकारी मशीनरी के कथित इस्तेमाल की जांच कब शुरू होती है। आरोप सही है या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन मामला सामने आने के बाद सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल और टेकेदार को कथित लाभ पहुंचाने के आरोपों ने परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।

जनता की सेवा ही हमारा मूल कर्तव्य, विधायक मीना सिंह ने निवास पर सुनीं जन-समस्याएं



उमरिया। मानपुर विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक सुश्री मीना सिंह जी जनसेवक बनकर 33 वर्षों से कर रही है जनता की सेवा विधायक सुश्री मीना सिंह ने अपने निवास पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्र के कोने-कोने से आए लोगों की समस्याओं को बारी-बारी से सुन करती हैं। इस जनसुनवाई के दौरान सड़क, बिजली, पानी ट्रांसफार्मर परिवर्तन, राजस्व विभाग सम्बंधित, वन विभाग जैसे अन्य कई शिकायतें सामने आती हैं जिसको। विधायक सुश्री मीना सिंह जी ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही फोन लगाकर समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश भी देती हैं और जनता की समस्या का निवारण कराने में कोई कसर नहीं छोड़ने सलाह अधिकारियों को देती हैं। जनसुनवाई के बाद विधायक मीना सिंह ने क्षेत्र का दौर पर भी निकल जाया करती हैं, जहां उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को जानती हैं और मौके पर ही समाधान कराती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारी विधायक मीना सिंह केवल जनसुनवाई तक ही सीमित नहीं रहतीं, बल्कि जमीनी स्तर पर जाकर जनता के सुख-दुख में हमेशा खड़ी रहती हैं।

माटी से बने गणेश, पर्यावरण की रक्षा का संदेश: सरवाही खुर्द में माटी गणेश प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न



तरुण शिक्षा संस्थान ने पर्यावरण संरक्षण का दिलाया संकल्प

बिरसिंहपुर पाली। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला उमरिया के तत्वावधान में ब्लॉक पाली के सेक्टर क्रमांक 01 अंतर्गत ग्राम सरवाही खुर्द में आज सेक्टर स्तरीय माटी गणेश - सिद्ध गणेश प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बने गणेश जी की स्थापना के लिए प्रेरित करना था। प्रशिक्षण में ग्रामीणों को मिट्टी से सुंदर और आकर्षक गणेश प्रतिमाएं बनाना सिखाया गया। इस अवसर पर जिला समन्वयक श्री रविन्द्र शुक्ला जी, ब्लॉक समन्वयक श्रीमती पुष्पा टेकाम, परामर्शदाता बृजेश तिवारी, संजय साहू, उषा प्रजापति, विद्यालय के प्राचार्य श्री गुलाब सिंह जी सहित विद्यालय के शिक्षकगण, CMCLDP छात्र एवं विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे। वहीं प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष सचिव मनीषा सिंह, अनुसुइया सिंह, दुर्गा सिंह, नीलम सिंह, पुष्पा सिंह, पान बाई, सुदर्शन सिंह, रेनू सिंह, राज बाई, नीरज सर, नवांकुर संस्था - तरुण शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा समिति की प्रमुख कृष्णा विश्वकर्मा, तरुण विश्वकर्मा, श्रवण महोबिया सहित प्रस्फुटन समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने संकल्प लिया कि इस बार गणेश उत्सव पर मिट्टी के गणेश जी की ही स्थापना कर पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देंगे।

जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन-परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई जारी

अवैध परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त, प्रकरण दर्ज किया गया

उमरिया। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए खनिज विभाग द्वारा लगातार सघन जांच एवं कार्रवाई की जा

रही है। खनि अधिकारी डॉ. विद्याकांत तिवारी के नेतृत्व में खनिज अमले द्वारा तहसील मानपुर क्षेत्र में जांच के दौरान दो वाहनों को अवैध रूप से खनिज गिट्टी का परिवहन करते हुए जप्त किया गया। जांच के दौरान सलेया तिराहा के पास ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 54 एए 0541 मय ट्रॉली को ई-टीपी में अंकित मात्रा से अधिक गिट्टी का परिवहन करते पाए जाने पर जप्त कर

पुलिस चौकी अमरपुर भेजा गया। इसी प्रकार ग्राम रक्शा के पास ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 18जेडई 0984 मय ट्रॉली को बिना अभिवहन पारपत्र/ई-टीपी के खनिज गिट्टी का परिवहन करते पाए जाने पर जप्त कर था। मानपुर में अप्रैल 2025 में सुपुर्द किया गया। दोनों प्रकरणों में मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का नियम, के



प्रावधानों के तहत गणेश पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग द्वारा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सघन जांच अभियान निरंतर है। इस दौन सहायक खनि अधिकारी प्रभात कुमार पट्टा एवं खनि निरीक्षक एन एस माकों भी उपस्थित रहे।



एसईसीएल रामपुर बटुरा में जय अम्बे कंपनी पर श्रमिकों के शोषण के आरोप

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर

एसईसीएल रामपुर बटुरा मेगा प्रोजेक्ट में ओबी का कार्य कर रही जय अम्बे कंपनी में कार्यरत श्रमिकों की समस्याएं एक बार फिर सामने आई हैं। श्रमिकों का आरोप है कि दिसंबर 2025 से उन्हें विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लंबे समय से शिकायतों के बावजूद समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। सबसे गंभीर मामला 30 से अधिक श्रमिकों के वेतन भुगतान से जुड़ा बताया जा रहा है। पीड़ित श्रमिकों ने एसईसीएल रामपुर बटुरा के मुख्य महाप्रबंधक से मामले में हस्तक्षेप कर उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण कराने की मांग की है। श्रमिकों का कहना है कि समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

समय पर वेतन नहीं मिलने का आरोप

श्रमिकों के अनुसार जय अम्बे कंपनी में काम करने वाले कई कर्मचारियों को नियमित रूप से समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। कुछ श्रमिकों का आरोप है कि काम छोड़ने के बाद भी उनका बकाया वेतन नहीं दिया गया। श्रमिकों का कहना है कि जब वे अपने मेहनताने की मांग करते हैं तो उन्हें अलग-अलग स्तर पर भेजा जाता है और भुगतान के लिए स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। श्रमिकों के मुताबिक वे लंबे समय तक कंपनी के लिए काम करते रहे, लेकिन काम समाप्त होने अथवा नौकरी छोड़ने के बाद बकाया राशि प्राप्त करने के लिए उन्हें लगातार चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे श्रमिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

पद के अनुरूप काम नहीं कराने का आरोप

पीड़ित श्रमिकों ने यह भी आरोप लगाया है कि कई कर्मचारियों से उनके पद और नियुक्ति के अनुरूप कार्य नहीं कराया जाता। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें अलग-अलग प्रकार के कार्यों में लगाया जाता है और कई बार कार्य की प्रकृति एवं जिम्मेदारी के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं। इसके साथ ही श्रमिकों ने सुरक्षा उपकरणों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कार्यस्थल पर आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। खनन एवं ओबी कार्य जैसे जोखिमपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर श्रमिकों ने विशेष ध्यान देने की मांग की है।

राष्ट्रीय अवकाश के भुगतान का भी मुद्दा

श्रमिकों ने राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में कार्य करने अथवा उससे संबंधित भुगतान को लेकर भी शिकायत की है। उनका कहना है कि उन्हें नियमानुसार मिलने वाले लाभों एवं भुगतान के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती और कई मामलों में भुगतान लंबित बताया जाता है। श्रमिकों का यह भी



आरोप है कि आए दिन उन्हें काम से बैठा देने की धमकी दी जाती है। कुछ श्रमिकों ने प्रबंधन स्तर पर अपशब्दों के प्रयोग का भी आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

काम छोड़ने के बाद वेतन रोकने का आरोप

श्रमिकों की सबसे बड़ी शिकायत उन कर्मचारियों को लेकर है जिन्होंने किसी कारणवश काम छोड़ दिया है। आरोप है कि ऐसे श्रमिकों का बकाया वेतन भुगतान नहीं किया गया। श्रमिकों का कहना है कि पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कई लोग मजबूरी में काम छोड़ते हैं, लेकिन काम छोड़ने के बाद मेहनत से अर्जित वेतन के लिए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिकों का कहना है कि यदि किसी कर्मचारी का वेतन किसी तकनीकी, प्रशासनिक अथवा अन्य कारण से लंबित है तो कंपनी को स्पष्ट रूप से कारण बताकर भुगतान की निश्चित समयसीमा तय करनी चाहिए।

जबरन अवकाश और नौकरी से निकालने की धमकी का आरोप

पीड़ित श्रमिकों ने जबरन अवकाश दिए जाने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई बार श्रमिकों को बिना स्पष्ट कारण काम से बैठा दिया जाता है। वहीं अपनी समस्याओं और वेतन की मांग उठाने वाले श्रमिकों को नौकरी से निकालने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। श्रमिकों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों के कारण कर्मचारी अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रखने से भी डरते हैं। उनका कहना है कि यदि श्रमिक अपनी मेहनत की मजदूरी की मांग करता है तो उसे डराने के बजाय उसकी शिकायत सुनकर नियमानुसार समाधान किया जाना चाहिए।

ननिहाल क्षेत्र में ही सहायक यंत्री को अतिरिक्त प्रभार, निष्पक्षता पर उठे सवाल

जैतहरी में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों

में असंतोष

रिश्तेदारी वाले गांवों में विकास कार्यों की

निगरानी को लेकर उठ रही आपत्तियां

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर | जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा सहायक यंत्री प्रवेश गौतम को जनपद पंचायत जैतहरी का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के बाद उनकी पदस्थापना को लेकर क्षेत्र में सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जैतहरी क्षेत्र उनके ननिहाल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा वेंकटराव, पटनाकरा, मेड़ियारास और धिरौल सहित अन्य क्षेत्रों में भी उनकी रिश्तेदारी होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में उच्च श्रेणियों के विकास कार्यों की तकनीकी निगरानी और शिकायतों की जांच का जिम्मा दिए जाने से निष्पक्षता को लेकर आशंकाएं पैदा हो रही हैं। ग्रामीणों का तर्क है कि सहायक यंत्री के पद पर रहते हुए निर्माण कार्यों का निरीक्षण, मूल्यांकन, भुगतान संबंधी तकनीकी प्रक्रिया और शिकायतों की जांच जैसे महत्वपूर्ण कार्य उनके दायरे में आते हैं। ऐसे में जहां अधिकारी के रिश्तेदार या परिचित रहते हों, वहां किसी भी निर्माण कार्य को लेकर शिकायत आने पर निष्पक्ष जांच की स्थिति पर सवाल खड़े हो सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को ऐसी स्थिति से बचने के लिए किसी ऐसे अधिकारी को प्रभार देना चाहिए, जिसका संबंधित क्षेत्र से व्यक्तिगत या पारिवारिक जुड़ाव न हो।

लंबित निर्माण कार्यों के बीच बड़ी चिंता

जैतहरी जनपद क्षेत्र में पहले से ही कई विकास एवं निर्माण कार्यों को लेकर ग्रामीण



स्तर पर शिकायतें और सवाल उठते रहे हैं। ऐसे समय में अतिरिक्त प्रभार मिलने से ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। उनका कहना है कि विकास कार्यों में तकनीकी स्वीकृति से लेकर स्थल निरीक्षण और गुणवत्ता परीक्षण तक की प्रक्रिया पारदर्शी होना जरूरी है। यदि अधिकारी का संबंधित क्षेत्र से व्यक्तिगत संबंध हो तो भले ही कार्य नियमानुसार किए जाएं, लेकिन उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठने की स्थिति बनी रह सकती है।

रिश्तेदारी वाले क्षेत्रों में प्रभार को लेकर आपत्ति

ग्रामीणों का आरोप है कि जैतहरी विकासखंड के अलावा वेंकटराव, पटनाकला, मेड़ियारास और धिरौल जैसे क्षेत्रों में भी सहायक यंत्री की रिश्तेदारी है। ऐसे में इन क्षेत्रों में होने वाले निर्माण कार्यों की निगरानी को लेकर ग्रामीण आशंकित हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन

ग्रामीणों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के चलते प्रशासन के सामने स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत महसूस की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि किसी अधिकारी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने के बजाय प्रशासन को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिसमें अधिकारी की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की गुंजाइश ही न रहे। उनका सुझाव है कि जैतहरी जनपद का अतिरिक्त प्रभार किसी अन्य सहायक यंत्री को सौंपा जाए, ताकि विकास कार्यों की निगरानी और शिकायतों की जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हो सके।

नियमों को लेकर भी उठ रहे सवाल

सहायक यंत्री को उनके ननिहाल और रिश्तेदारी वाले क्षेत्र में अतिरिक्त प्रभार दिए जाने को लेकर शासन के पदस्थापना संबंधी नियमों का हवाला भी दिया जा रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि अधिकारियों को निजी अथवा निष्पक्षता पर सवाल उठाने की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन

संबंधित नियम की सटीक वैधानिक स्थिति और इस मामले में उसकी लागू होने की स्थिति प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया जाना बाकी है। यही वजह है कि जिला पंचायत के आदेश के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या अतिरिक्त प्रभार देने से पहले अधिकारी के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखा गया था। यदि नियमों में ऐसी पदस्थापना पर रोक या प्रतिबंध है तो उसकी अनदेखी क्यों की गई और यदि ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है तो जिला प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

सवाल प्रभार देने की मंशा पर नहीं, व्यवस्था की पारदर्शिता पर

ग्रामीणों का कहना है कि मामला किसी अधिकारी विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि विकास कार्यों की पारदर्शिता और निष्पक्ष निगरानी से जुड़ा है। उनका सवाल है कि जब जैतहरी में अन्य अधिकारी उपलब्ध हो सकते हैं तो ऐसे अधिकारी को ही अतिरिक्त प्रभार क्यों दिया गया, जिसका क्षेत्र से पारिवारिक जुड़ाव बताया जा रहा है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की समीक्षा कर जैतहरी जनपद पंचायत में किसी ऐसे सहायक यंत्री को अतिरिक्त प्रभार दिया जाए, जिसका संबंधित क्षेत्र से निजी या पारिवारिक संबंध न हो। इससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, शिकायतों की जांच और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रहेगी तथा भविष्य में किसी भी अधिकारी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने की स्थिति से बचा जा सकेगा।

भाजपा मंडल राजनगर की मासिक कामकाजी बैठक आमाडांड में संपन्न

सेवा संकल्प अभियान प्रशिक्षण सहित आगामी

संगठनात्मक कार्यक्रमों पर हुई चर्चा

हरिभूमि न्यूज राजनगर | भारतीय जनता पार्टी मंडल राजनगर की मासिक कामकाजी एवं सेवा संकल्प अभियान प्रशिक्षण बैठक बुधवार को ग्राम आमाडांड स्थित पंचायत भवन में मंडल अध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संपठन की आगामी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में अभियान के प्रभारी जितेंद्र भट्ट एवं मंडल प्रभारी अमृतलाल केवट की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी एवं पींडत दीनदयाल उपाध्याय के चित्रपर पुष्प अर्पित कर की गई। बैठक के दौरान भाजपा की नवीन जिला कार्यसमिति में घोषित सदस्यों के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता गजेंद्र सिंह सिकरवार, राजेश कलसा, श्रीमती द्रौपदी प्रजापति एवं श्रीमती सरला सिंह तथा जिला कार्यसमिति के विशेष आमंत्रित सदस्य डॉ. सुनील कुमार चौरसिया, अध्यक्ष नगर परिषद दुमरकछार, यशवंत सिंह, अध्यक्षनगर परिषद बनगावां एवं मनोज सिंह, सांसद प्रतिनिधि, सहित श्रीमती संगीता साहू,अध्यक्ष महिला मोर्चा मंडल राजनगर सुश्री कंचना मेहता एवं धर्मेन्द्र सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा का राजनगर मंडल की ओर से सम्मान किया गया। बैठक में 17 सितंबर से प्रस्तावित भाजपा के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को दी गई। साथ ही बूथ अध्यक्षों एवं शक्ति केंद्र प्रभारियों से संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और बूथ का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। इसी दौरान बूथ क्रमांक 156 के अध्यक्ष गणेश



साहू द्वारा राम सिंह को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राम सिंह का फूलमाला एवं अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। बैठक में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी कार्यकर्ताओं को दी गई, ताकि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा सके। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री सचिन द्विवेदी ने किया। समापन अवसर पर आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की गई। ग्राम आमाडांड में आयोजित कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था में किसान मोर्चा मंडल राजनगर के अध्यक्ष मूलचंद गुता (चुकान) का विशेष योगदान एवं सहयोग रहा। बैठक में पार्षद पावर्ती सिंह, अरविंद सिंह परिहार, राजेश जायसवाल, भुजील गुता, शिव मूरत केवट, पुष्पराज सिंह, गोपाल चौधरी, दुलीचंद धनवार, मनीष शुक्ला, रविदास चौधरी, चंद्रशेखर द्विवेदी, पंकज कुमार शर्मा (मंडल मीडिया प्रभारी) सहित मंडल के पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी, विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान आज बटुरा में आयोजित होगा कैम्प

मैदानी भ्रमण कर शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण करेंगे अधिकारी

लंबित प्रकरणों के निराकरण पर रहेगा विशेष जोर

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के अंतर्गत आज 11 सितम्बर को आईटीआई बटुरा में कैम्प आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत आमजन की समस्याओं के निराकरण, शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मैदानी स्तर पर शासकीय संस्थाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का भ्रमण एवं विभिन्न संस्थाओं का निरीक्षण किया जाएगा। कलेक्टर रत्नाकर झा ने अभियान से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कैम्प के पूर्व संबंधित क्षेत्र में सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित



आवश्यक कार्यवाही करते हुए यथासंभव मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित कराया जाए। अभियान के तहत अधिकारी क्षेत्र की विभिन्न शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। इनमें स्कूल, महाविद्यालय, पुलिस थाना, राशन दुकान, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, छात्रावास, कृषि उपज मंडी तथा निर्माणाधीन वृहद परियोजनाओं सहित अन्य संस्थाएं शामिल रहेंगी। निरीक्षण के दौरान संस्थाओं में उपलब्ध व्यवस्थाओं, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया जाएगा और आवश्यक सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया

जाएगा। कैम्प दिवस के प्रथम चरण में अधिकारी पूर्व निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार मैदानी क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे तथा दोपहर 12:30 बजे तक कैम्प स्थल पर पहुंचेंगे। कैम्प में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं मैदानी अमला उपस्थित रहकर नागरिकों से प्राप्त आवेदनों एवं समस्याओं के निराकरण की कार्यवाही करेंगे। कैम्प की समाप्ति तक अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। कैम्प में प्राप्त आवेदनों का संधारण एवं निराकरण जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों को जनआकांक्षा पोर्टल पर दर्ज कर संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। साथ ही अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण की संक्षिप्त रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। कैम्प के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनूपपुर सुश्री प्राची अग्रवाल को नोडल अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर रवि गुप्ता को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

नायब तहसीलदार की मौजूदगी में रेस्क्यू दल ने गहरे पानी से निकाला शव

धनपुरी पुलिस ने शुरू की जांच

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। घर से करीब 200 मीटर दूर तालाब में अन्य बच्चों के साथ नहाने गए 5 वर्षीय बालक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खोह के सोनहा गांव की है। मंगलवार शाम से लापता बालक की तलाश बुधवार सुबह रेस्क्यू अभियान चलाकर की गई। नायब तहसीलदार बुद्धार की मौजूदगी में एसडीआईआरएफ शहडोल की टीम ने तालाब के गहरे पानी में खोजबीन कर बालक का शव बरामद किया। शव धनपुरी पुलिस को सौंप दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के



लिए अस्पताल भेजा। ग्रामीणों के अनुसार सोनहा निवासी मोहन यादव का 5 वर्षीय पुत्र विनोद यादव मंगलवार शाम मोहल्ले के चार-

नहीं लौटने पर पिता और परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान तालाब के बाहर चट्टान पर बालक की शर्ट पड़ी मिली। इससे परिजनों

को उसके तालाब में डूबने की आशंका हुई। तत्काल धनपुरी थाना पुलिस और बुद्धार तहसील प्रशासन को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद बुधवार सुबह बुद्धार में पदस्थ नायब तहसीलदार मनोज सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में एसडीआईआरएफ शहडोल के रेस्क्यू दल ने तालाब में खोजबीन शुरू की। काफी तलाश के बाद टीम ने गहरे पानी के अंदर से 5 वर्षीय विनोद यादव का शव बरामद किया। शव बाहर निकालकर धनपुरी पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। बालक की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है, वहीं घटना के बाद गांव में भी शोक का माहौल है।